खा जाते हैं। किसी भी देश की G.D.P. यानी अर्थव्यवस्था के तीन मुख्य आधार होते हैं। अग्रीकल्चर, इन्डस्ट्री एवं सर्विसेज़। हमारे जल, जंगल, जमीन, भू-सम्पदा एवं बौद्धिक सम्पदाओं का विदेशी कंपनियाँ पूरा शोषण व दोहन कर रही हैं। आज रिटेलर से लेकर शेयर मार्केट तक, हैल्थ, एजुकेशन, रिसर्च एण्ड डेवलप्मेन्ट, मीडिया, रक्षा सामान, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से लेकर हमारे देवी-देवता, बच्चों के खिलौने, टी.वी., गाड़ी, मोबाईल, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट से लेकर जीवन की हर जरूरत का हर सामान विदेशी कंपनियाँ बेच रही हैं। एक तरह से हमने अपना पूरा देश विदेशी कंपनियों के हाथों में गिरवी रख दिया है। अमेरिका, चीन, जर्मनी व जापान आदि स्वदेशी के रास्ते पर चलकर खुद को स्वावलम्बी बना रहे रहे हैं। हम भारतवासी भी बिना स्वदेशी के अपने देश को स्वावलम्बी नहीं बना सकते।

3. **सामाजिक षड्यन्त्र :** सामाजिक रूप से देश का कौन नेतृत्व करेगा, सामाजिक आवाज के रूप में किसे सुना जायेगा। किसे आर्थिक, राजनैतिक व अन्य विषयों में विशेषज्ञ का दर्जा मिलेगा। कौन विश्वसुन्दरी होगी? शोश्यल एक्टिविस्ट के रूप में देश में किसे स्थापित करना है। इसके लिए विदेशी सरकारें विदेशी कंपनियाँ एवं विदेशी फाउंडेशन्स भारतीय एन.जी.ओ. को दान करती हैं। जो विदेशी कंपनियाँ अमेरिका व यूरोप के हितों में काम करें, उसे बाकायदा अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जाता है। जिससे उनकी देश में प्रतिष्ठा बढ़े, उन्हें विश्वसुन्दरी आदि के पुरस्कार दिये जाते हैं, जिससे कि विदेशी कंपनियों का सामान बेचने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा सके। ऐसे कानून पास करवाने के लिए भी विदेशी कंपनियाँ एन.जी.ओ. को दान देती हैं, जिससे उस देश से उनको जरूरी सूचनाएँ प्राप्त करने में आसानी हो और सरकारी संस्थाएँ कमजोर पड़ें जिससे विदेशी कंपनियों व प्राईवेट क्षेत्र के बड़े-बड़े पूंजीपति अपना स्वार्थ सिद्ध कर सकें। ये सब कार्य इतनी होशियारी से किया जाता है कि इनके खिलाफ उठाने वाले व्यक्ति को ही ये अपराधी या दोषी के रूप में प्रमाणित कर देते हैं।

4. **नैतिक षड्यन्त्र :** हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता, संयम, सदाचार एवं प्राचीन मूल्य, आदर्शों व गौरव के सभी प्रतीकों, हमारे महापुरुषों, देवी-देवताओं, गौ, गंगा, गायत्री व वेदों से लेकर भगवान राम, कृष्ण व शिव आदि महापुरुषों के बारे में झूठी बातें प्रचारित करना। महापुरुषों को काल्पनिक बताना तथा रामायण व महाभारत आदि महाकाव्यों को उपन्यास बताकर अपने प्राचीन गौरव को झुठलाने का प्रयास करना। टी.वी. पर ऐसे सीरियल व मनोरंजन के नाम पर ऐसी फिल्में बनवाना व उसमें भोग विलास व दुराचार को ग्लैमर के साथ प्रस्तुत करके देश के लोगों के पुरुषार्थ व चरित्र को नष्ट करने का एक बहुत बड़ा षड्यन्त्र रचा जाता है। ऐसे अश्लील कार्यक्रमों के लिए विज्ञापन खूब मिलें, इसके लिए टी.आर.पी. तय करने वाली कंपनी भी 100% विदेशी नियन्त्रण वाली है। वह टी.आर.पी. बताने वाली विदेशी कंपनी परोक्ष रूप से देश के सभी चैनलों का नियन्त्रण करती हैं। देश की भाषा, भेषज, भजन, भोजन, भाव व संस्कृति के विनाश का बहुत बड़ा षड्यन्त्र चल रहा है। देश के चरित्र को नष्ट करने का ये चक्रव्यूह हमने नहीं तोड़ा तो देश की बहुत बड़ी हानि हो रही है और आगे बड़ा खतरा आने वाला है। इसी तरह देश में जाति, धर्म व मजहब के नाम पर भी बहुत प्रकार के षड्यन्त्र चलते रहते हैं कुछ लोग अज्ञान में भी इस प्रकार का काम करते हैं। परन्तु हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि चीन इन्हीं लोगों का सहारा लेकर भारत को 50 से अधिक टुकड़ों में बांटना चाहता है। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप व कुछ अन्य देश भी धार्मिक क्षेत्रीय व भाषीय आधार पर देश के विभाजन के बहुत गहरे षड्यन्त्र कर रहे हैं।

आंदोलनों का नेतृत्व करने वाले कार्यकत्ताओं को इन सब बातों का गंभीरता से ध्यान रखकर सावधानी पूर्वक खुद इन षड्यन्त्रों से बचना चाहिए व सामान्य कार्यकर्त्ताओं को भी सावधान करते रहना चाहिए।

☛ **आपका योगदान :** 11 करोड़ से अधिक लोगों को श्रद्धेय स्वामी जी द्वारा शिविरों में प्रत्यक्ष प्रशिक्षण तथा दुनियाँ के 200 से अधिक देशों में योग व भारतीय संस्कृति को प्रतिष्ठा मिली है। योग, आयुर्वेद व स्वदेशी के राष्ट्र व विश्वव्यापी रचनात्मक सेवा कार्य के साथ-साथ राष्ट्रव्यापी आन्दोलन भी चल रहा है।

हम बड़े कॉर्पोरेट हाउस, सरकार, विदेशी कम्पनियों व बेईमान लोगों के पैसे के बल पर सेवा कार्य व आन्दोलन नहीं चलाना चाहते। **यह अभियान देश के लोगों के सहयोग से देश के लिए चला रहे हैं। हम अन्तिम व आम आदमी के सहयोग से 121 करोड़ आम लोगों की इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं।** सेवा, तप, त्याग व चरित्र के बल पर हमारा ये अभियान या ईश्वरीय काम अवश्य पूरा होगा।

कालाधन लाना है, देश को बचाना है। भ्रष्टाचार मिटाना है, देश को बचाना है।।

जब एक योगी-योद्धा, एक संन्यासी, एक संत अपना सब कुछ दांव पर लगाकर 121 करोड़ भारतीयों के सुख, स्वाभिमान व सम्मान के लिये संघर्ष कर रहा है तो क्या आप मौन रहेंगे? क्या आप इस काम के लिये श्रद्धेय स्वामी जी को अकेला ही जूझने के लिये, लड़ने के लिये, मरने के लिये छोड़ देंगे ? यदि नहीं तो आइये! आप भी अपने भारत को महाशक्ति बनाने के राष्ट्रव्यापी अभियान से जुड़िये!

आह्वान :- राष्ट्रहित में इस पत्रक को अधिक से अधिक संख्या में फोटोकॉपी या प्रिन्ट करवाकर गाँव-गाँव व घर-घर में वितरित करें। मौखिक रूप से भी जन-साधारण में कालेधन व भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण के लिए जागरुकता पैदा करें।

आन्दोलन व पतंजलि योगपीठ से जुड़ने के लिए हमारी ई-मेल : divyayoga@rediffmail.com अथवा फोन: 01334-240008, 248888, 244107, 246737 व फैक्स : 01334-244805, 240664 पर सम्पर्क कर सकते हैं। आप पतंजलि योगपीठ, हरिद्वार आकर भी सीधे सम्पर्क कर सकते हैं। पूज्य स्वामीजी के नवीनतम विचार जानने के लिए हमारी वेब-साइट: www.bharatswabhimantrust.org और ब्लॉग: www.swami-ramdev.com को निरन्तर पढ़ें, फेसबुक: www.facebook.com/swami.ramdev को Like करें और ट्वीटर: www.twitter.com/yogrishiramdev को अवश्य Follow करें।

कालाधन, भ्रष्टाचार व अन्याय पूर्ण भ्रष्ट व्यवस्था के विरुद्ध

9 अगस्त के राष्ट्रव्यापी आन्दोलन की संक्षिप्त रूपरेखा

कालाधन वापस लाने की मुख्य प्रक्रियाएँ–

कालाधन देश को दिलाने के लिए दो महत्वपूर्ण पहलु हैं–एक राजनैतिक ईच्छाशक्ति व ईमानदारी तथा दूसरा कानूनी प्रक्रिया में नए प्रावधान। दोनों के बारे में हम संक्षेप से बता रहे हैं, जिससे किसी भी देशवासी को इस विषय में मूलभूत सही जानकारी हो सके और उनको कोई स्वार्थ व षड्यन्त्र करके भ्रमित न कर सके। हमारा यह आंदोलन खाली सुहाना सपना या कल्पना नहीं है, अपितु सबसे बड़ी हकीकत है।

सरकार के पास पुलिस, आई.बी., रॉ, विजिलेंश व इंटेलीजेंस एजेन्सियाँ तथा अलग-अलग टैक्सेशन डिपार्टमेन्ट्स आदि लगभग 20 लाख से अधिक लोगों के इस सरकारी तन्त्र के माध्यम से केन्द्र सरकार को सब कुछ पता है कि कौन हवाला कर रहा है? कौन अण्डर इन्वायजिंग, ओवर इन्वायजिंग तथा अन्य प्रकार की बिलिंग में हेरा-फेरी कर रहा है? कौन बैंकिंग के गोपनीयता कानूनों का दुरुपयोग करके पैसा बाहर भेज रहा है? कौन रिश्वत ले रहा है? कहाँ-कहाँ घोटाले हो रहे हैं? किस-किस विभाग में कितनी लूट मची हुई है? सरकार यदि ईमानदारी व मजबूत राजनैतिक ईच्छाशक्ति से काम करे तो एक ही दिन में कालेधन की अर्थव्यवस्था पर सरकार लगाम लगा सकती है। हमने सभी पार्टियों की केन्द्र में सरकार देखी है, परन्तु किसी भी राजनैतिक पार्टी ने ईमानदारी से ये कदम नहीं उठाए। यदि राजनैतिक दलों में ईमानदारी होती तो यह कालाधन जमा ही नहीं होता। अत: अब तो एक ही समाधान नजर आता है–या तो वर्तमान केन्द्र सरकार ईमानदारी से कालाधन देश को दिलाकर 121 करोड़ लोगों को न्याय दिलाये या फिर सत्ता से हट जाये और ईमानदार लोग ही संसद में जायें तथा कालाधन देश को दिलायें व भ्रष्टाचार मिटायें।

दूसरी कानूनी प्रक्रियाएँ हैं, जिनसे हम देश में 100% आर्थिक पारदर्शिता ला सकते हैं और इस कालेधन व भ्रष्टाचार पर नकेल कस सकते हैं। कालाधन देश को दिलाने की मुख्य कानूनी प्रक्रियाएँ–

1. केन्द्र सरकार **विदेशों में जमा कालेधन** व अवैध सम्पत्ति को **राष्ट्रीय सम्पत्ति** घोषित करे।
2. विदेशों में जमा कालेधन व अवैध सम्पत्ति का पता लगाने के लिए **'बेनेफिशियल ऑनरशिप'** के डिक्लेरेशन का प्रावधान करे, जिससे विदेशी पूंजीनिवेश के नाम पर आने वाले धन के मूल स्रोत व उसके वास्तविक मालिकों के बारे में पता लग जायेगा तथा इससे 100% आर्थिक पारदर्शिता आयेगी। इस प्रावधान से कालाधन किन लोगों का है, इसके बार में पूरी सच्चाई सामने आ जायेगी। अभी 'शैल कम्पनीज' (कालाधन छुपाने के लिए बनाये जाने वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस) व अन्य प्रक्रियाओं से जो पैसा देश में आ रहा है, उसके वास्तविक मालिकों के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा सकते। जो विदेशी पूंजीनिवेश के नाम पर बाहर से देश में धन ला रहे हैं व देश में जमा अवैध धन-सम्पत्ति तथा विदेशों में भी जमा शेष कालाधन व अवैध सम्पत्ति मुख्य रूप से इन्हीं लोगों की है। अत: बैनेफीशियल ऑनरशिप के प्रावधान के बिना, कालाधन किन लोगों का है, इसका पता लगाया ही नहीं जा सकता तथा इस प्रावधान के होने पर कोई भी बड़ा भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता। इस प्रावधान से विदेशी पूंजी निवेश यानी F.D.I. के भी मूलस्रोत व वास्तविक मालिकों के बारे में भी पूरी जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। F.D.I. कालेधन की चाबी है या केन्द्र बिन्दु है। इसके खुलासे से देश विदेशों में जमा कालेधन के राज़ खुल जायेंगे।
3. गत 30 वर्षों में शीर्ष राजनैतिक पदाधिकारी जैसे विधानसभा व लोकसभा सदस्य, प्रथम श्रेणी के सरकारी अधिकारी व बड़े उद्योगपतियों पर बिना किसी पक्षपात के समान रूप से **प्रिवेंशन ऑफ करप्शन** और **मनी लॉडरिंग एक्ट्स तथा पॉलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन्स** के तहत नये प्रावधान करके एक **जनरल पर्पज़ एफ.आई.आर.** दर्ज करके उनकी व उनके रिश्तेदारों की विदेशों में जमा अवैध धन-सम्पत्ति का पता लगाया जाये।
4. **प्रोमेसरी-नोट** तथा **पार्टिस्पेटरी नोट** (पी.एन. रूट) की आर्थिक व्यवस्था, जिससे काले धन का कारोबार पनप रहा है और लाखों करोड़ रुपये के काले-धन को भ्रष्टाचारी लोग इस जरिये से सफेद कर रहे हैं, इन दोनों प्रक्रियाओं को तुरन्त बन्द किया जाये। विदेशों में कालाधन जमा करने वाले लोगों के बारे में **इमिग्रेशन विभाग, वीजा विभाग, विदेश मंत्रालय, विभिन्न देशों के दूतावासों के माध्यम से जानकारियां जुटाकर** टैक्स हैवन्स में बार-बार जाने वाले व्यक्तियों के बारे में पता लगाया जाये साथ ही इंटरनेशनल इंफोरमेशन गेट-वेज़ पर टैक्नीकल सर्विलांस द्वारा इन्वेस्टिगेशन करके देश-विदेश में बैठकर जो लोग कालेधन का धन्धा चला रहे हैं, उनके बारे में पता लगाया जाये।
5. बैंकिंग सीक्रेसी कानूनों (लॉज़) में आमूलचूल परिवर्तन करके तथा स्वीटज़रलैण्ड, अमेरिका, इंग्लैण्ड, इटली आदि के विदेशी बैंक जो भारत में खुले हुए हैं और वे धड़ल्ले से कालाधन जमा कर रहे हैं, इन विदेशी बैंकों की टैक्सहैवन्स में चल रही शाखाओं (सब्सीडरीज़) के बारे में पूरा ब्यौरा देने का प्रावधान करके कालेधन पर लगाम लगाई जाये।
6. विदेशों में जमा कालेधन के बारे में सरकार के पास उपलब्ध **36 हजार सूचनायें, लगभग 9 हजार 900 विदेशी ट्रांज़ॅक्शन्स** और विदेशों में खाते रखने वाले अभी तक ज्ञात कम से कम 3000 के लगभग नाम सार्वजनिक किये जायें और इन लोगों के पास जितना भी कालाधन है, उसे तत्काल देश को दिलाया जाये।
7. विदेशों में जमा कालेधन को वापस लाने के साथ-साथ देश में ही जमा लाखों करोड़ रुपये के कालेधन की अर्थव्यवस्था को समाप्त करने के लिए देश की आर्थिक नीतियों व कर प्रणाली में एक बहुत बड़ा सकारात्मक सुधार किया जाये। किसी भी देश की आदर्श अर्थव्यवस्था के लिए उसकी जी.डी.पी. की 2 से 3 प्रतिशत छोटी करेंसी की ही आवश्यकता होती है। शेष अर्थव्यवस्था टैक्नॉलॉजि बेस्ड बैंकिंग ट्रांज़ॅक्शन, चैक, ड्राफ्ट, क्रेडिट, डेबिट व स्मार्ट कार्ड, मोबाइल ट्रांसफर आदि से चलती है और ये सभी ट्रांजक्शंस ट्रेसेबल होते हैं और इससे

कालेधन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो जाती है। जबकि भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 20% करेंसी है और वह भी 97% बड़ी करेंसी है। अत: **500 व 1000 रुपये** के बड़े नोट वापस लेकर कालेधन, भ्रष्टाचार, कालेधन्धे, महंगाई, गरीबी, नकली करेंसी, नक्सलवाद व आतंकवाद आदि सभी अनैतिक व अवैध कार्यों पर अंकुश लगायें। भारत की कर प्रणाली भी बहुत ही दोषपूर्ण है। इसमें भी एक बहुत बड़े व्यापक सुधार की आवश्यकता है।

ये 400 लाख करोड़ रुपये का कालाधन भी लाना है साथ ही भ्रष्टाचार को भी मिटाना है तथा लगभग 20 हजार लाख करोड़ रुपये की भू-सम्पदाओं को भी बचाना है। भारत में कोयला, लोहा, सोना, चांदी, हीरा, गैस व पैट्रोल आदि 89 प्रकार के मिनरल्स (भू-सम्पदाएँ) है। इनकी कुल कीमत लगभग 20 हजार लाख करोड़ रुपये है। यदि भ्रष्टाचार को हमने खत्म नहीं किया और भू-सम्पदा की लूट को नहीं रोका तो भारत माता की हिरण्यगर्भा कोख खाली हो जायेगी। यदि हम केवल कोयले को ही बचाकर रखते हैं तो भारत आज जहां खड़ा है, उससे 100 गुणा आगे पहुँच जायेगा।

भ्रष्टाचार मिटाने हेतु तीन मुख्य प्रक्रियाएँ–

1. मजबूत लोकपाल बिल बनाकर बड़े लोगों के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना। लोकपाल की नियुक्ति व निष्कासन की निष्पक्ष प्रक्रिया होनी चाहिए तथा सी.बी.आई. लोकपाल के अधीन होनी चाहिए।
2. स्थापित न्याय व कानूनी व्यवस्था, जिसमें पुलिस व प्रशासन से लेकर न्याय व्यवस्था तक लाखों सरकारी कर्मचारी व अधिकारी से लेकर जजों तक जो प्रतिदिन आम लोगों को न्याय देने का काम करते हैं, इसे प्रामाणिक, पारदर्शी व जवाबदेह बनाना।
3. शिक्षा में संस्कार व उच्च आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश करके देश के बच्चों व जवानों में सदाचार को बढ़ाना। समाज के हर क्षेत्र में नैतिक मूल्यों व उच्च आदर्शों को प्रतिष्ठापित करना। सदाचार को बढ़ाए बिना भ्रष्टाचार को पूरी तरह से नहीं मिटा सकते। बच्चों को जब बचपन से ही उच्च संस्कार व सदाचार की शिक्षा मिलेगी तो वे जीवन में न तो कभी भ्रष्टाचार करेंगे और न ही सहेंगे।

हमारे देश का लगभग 400 लाख करोड़ रुपये का कालाधन देश-विदेशों में जमा है तथा देश गरीबी, महंगाई व बेरोजगारी आदि समस्याओं से जूझ रहा है। आज पूरा राष्ट्र एक बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। पूरे देश में त्राहि-त्राहि मची हुई है। सभी जाति, वर्ग व सभी मजहबों के लोग भ्रष्ट-व्यवस्था से त्रस्त हैं। देश के 121 करोड़ लोगों में एक बहुत बड़े परिवर्तन के लिए जबरदस्त आक्रोश है। भारत माता के सीने को देश के ही कुछ गद्दारों ने धोखा व विश्वासघात करके लहू-लुहान कर दिया है। ऐसे में करोड़ों देशभक्त नागरिकों के हृदय में जुनून, आक्रोश, शोर्य व स्वाभिमान उमड़ रहा है और उनका खून खौल रहा है। जब कालेधन, भ्रष्टाचार, महंगाई व गरीबी के मुद्दे पर मिस्र, लीबिया व ट्यूनेशिया में प्रलयंकारी परिवर्तन हो सकता है तो भारत में शान्तिपूर्ण व अहिंसक परिवर्तन क्यों नहीं। अब और कितने दिनों तक लुटते रहेंगे तथा गरीबी, भूख व अपमान की जिंदगी जीते रहेंगे। आज जब देश को लूटने में यदि कुछ चन्द लोग हैं तो भारत माता की रक्षा के लिए करोड़ों लोगों के खड़े होने की आवश्यकता है।

हमारा देश कमजोर नहीं है, हमारी किस्मत (भाग्य) या कर्म भी खराब नहीं तथा हम अपनी जाति, वर्ग या मज़हब के कारण गरीब, अनपढ़ या बेरोजगार नहीं हैं, बल्कि कालाधन, भ्रष्टाचार व भ्रष्ट-व्यवस्था के कारण हमारी व हमारे देश की यह दुर्दशा हुई है।

व्यवस्था परिवर्तन के मुख्य बिन्दु :

(1) राष्ट्रीय किसान आय आयोग का गठन (2) समान शिक्षा व्यवस्था (3) समान चिकित्सा व्यवस्था (4) चुनाव सुधार (5) राष्ट्रीय प्रबन्धन नीति (6) अंग्रेजी काले कानून खत्म करवाना तथा न्यायपूर्ण स्वदेशी व्यवस्था की स्थापना करना।

नोट : *व्यवस्था परिवर्तन के उपरोक्त मुद्दों पर अधिक जानकारी हेतु आप हमारी वेबसाईट www.bharatswabhimantrust.org देख सकते हैं।*

अब यह निर्णय देश के जिम्मेदार व जागरूक नागरिकों को लेना है **कि आप देश को लूटने वाले चोरों व गद्दारों के साथ खड़े होगें अथवा देश को बचाने, कालाधन लाने व भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आंदोलन के साथ खड़े होंगे?**

☛ **आज का भारत :** 10 लाख 67 हजार करोड़ रुपये का कोयला घोटाला या घाटा (वास्तविक कोयला घोटाला 200 लाख करोड़ रुपये का हुआ है तथा देश में कुल ज्ञात कोयला 1144 लाख करोड़ रुपये का है), 1 लाख 76 हजार करोड़ रुपये का 2जी घोटाला, 70 हजार करोड़ रुपये का कॉमन वैल्थ घोटाला, हजारों करोड़ का आदर्श घोटाला, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोटी (अनाज), कपड़ा व मकान से लेकर पशुचारा तक चारों तरफ ज्ञात-अज्ञात घोटालों की भरमार है, ऐसी केन्द्र सरकार को क्या सत्ता में बने रहने का नैतिक व संवैधानिक अधिकार है? वोट मिलने व बहुमत होने पर भी यदि सरकार देश के साथ न्याय नहीं कर पा रही है तो वह सत्ता में रहने का हक खो देती है।

☛ **देश व देशवासियों की वास्तविक शक्ति व सम्पत्ति :** भारत की लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर की भूमि, कोयला, लोहा, सोना, चाँदी, हीरा, एलुमीनियम, गैस व तेल आदि 89 प्रकार की भू-सम्पदाएं हैं जो लगभग 20 हजार लाख करोड़ रुपये की सम्पत्ति है। इसके अलावा जल, जंगल, जमीन, जड़ी-बूटियों व लगभग 60 करोड़ युवा शक्ति के साथ 121 करोड़ लोगों की मानव संसाधन के रूप में अपरिमित शक्ति हमारे राष्ट्र में है। <u>जब इन भू-सम्पदाओं में ही सबको बराबर का हक मिलेगा और देशवासियों में इसका न्यायपूर्ण वितरण होगा, तो एक-एक व्यक्ति को लगभग 2-2 करोड़ और एक-एक परिवार को लगभग 10-10 करोड़ रुपये मिलेंगे</u> और इसी प्रकार जब कालाधन देश को मिलेगा, तो एक-एक परिवार को लगभग 15 से 20 लाख रुपये मिलेंगे अथवा सम्पत्ति पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनका स्वामित्व होगा और हिन्दुस्तान में एक भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा। यदि इस कालेधन को गाँव व जिले के विकास के हिसाब से देखें तो एक-एक गाँव के हिस्से में लगभग 100 करोड़ तथा एक-एक जिले के हिस्से में लगभग 60 हजार करोड़ रुपये आयेंगे। लगभग 400 लाख करोड़ रुपये अंग्रेजों व अन्य विदेशी लुटेरों ने लूटे, आजादी के बाद लगभग 400 लाख करोड़ रुपये अपने ही देश के कुछ बेईमान नेताओं ने खुद लूटे व अन्यों से लुटवाए तथा अब भी देश की आधी से ज्यादा अर्थव्यवस्था पर विदेशी कम्पनियों, पूंजीवाद व सामन्तवाद का साम्राज्य या कब्जा है। ये लूट बन्द करनी है तथा देश के सब वर्ग व मजहब के लोगों को आर्थिक व सामाजिक न्याय दिलाना है। हम भारतीय अपनी जाति व मजहब आदि के कारण गरीब

नहीं हैं। अपितु इसका मूल कारण है कालाधन, भ्रष्टाचार व अन्यायपूर्ण भ्रष्ट व्यवस्थाएं हैं। देश के 121 करोड़ लोगों को ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार, नैसर्गिक, मौलिक व संवैधानिक कानूनन अधिकार हम किसी भी कीमत पर दिलवायेंगे।

☛ **कालाधन कितना है? :** इस देश में वास्तविक रूप से लगभग 1 लाख टन सोना है, जिसकी कीमत लगभग 300 लाख करोड़ रुपये है, इसमें लगभग 80% कालाधन ही है, क्योंकि लगभग 20 हजार टन सोना ही वैध रूप से देश में है। माइनिंग, रीयल स्टेट, नशा उद्योग, कालाबाजारी, राजनीति, शिक्षा, चिकित्सा व कानून आदि के क्षेत्र में भी कम से कम बराबर का या दोगुना कालाधन है। कुल मिलाकर देश की अर्थव्यवस्था का वास्तविक आकार लगभग 500 लाख करोड़ रुपये है, जबकि जी.डी.पी. के रूप में लगभग 80 से 100 लाख करोड़ रुपये की ही अर्थव्यवस्था दिखाई जा रही है। देश-विदेश में जमा शेष ये 400 लाख करोड़ से भी अधिक कालाधन 1% से 5% कुछ बड़े, बुरे व बेईमान लोगों के पास जमा है। इसी कालेधन को 95% से 99% आम लोगों तक पहुँचाना है। इसमें कुछ ब्लैकमनी है, कुछ ग्रे-मनी है, कुछ लूट, चोरी व रिश्वतखोरी व घोटालों आदि का पैसा है, इसमें से प्रतिवर्ष कुछ पैसा देश के भीतर जमा होता रहता है या घूमता रहता है तथा कुछ देश के बाहर विदेशों में चला जाता है। पूरी दुनियाँ की अर्थव्यवस्था वैध रूप में लगभग 3 हजार लाख करोड़ रुपये की है तथा इतना ही अर्थात् लगभग 3 हजार लाख करोड़ अवैध या कालाधन है। अमेरिका व इंग्लैण्ड आदि इस कालेधन का इस्तेमाल कर रहे हैं।

☛ **कालेधन व मजबूत लोकपाल की केन्द्र सरकार से ही मांग क्यों? :** क्योंकि देश के लोकतन्त्र में संविधान ने कालाधन को वापस दिलाने के लिए कानूनी प्रावधान करने का तथा भ्रष्टचार मिटाने हेतु मजबूत लोकपाल बिल बनाने का एकमात्र अधिकार केन्द्र सरकार को दिया हुआ है। जैसे किसी भी अपराधी को गिरफ्तार करने का अधिकार पुलिस को ही है चाहे आम आदमी हो या प्रधानमंत्री। इसी तरह रजिस्ट्री करने का अधिकार रजिस्ट्रार को ही है। इसी तरह कानून संशोधन करके कालाधन वापस लाने का एकमात्र अधिकार केन्द्र सरकार को ही है। और लोकतन्त्र में सरकार के ऊपर जनता होती है। अत: जो जनता चाहती है, वह सरकार को करना ही पड़ेगा। जनता चाहती है कालाधन आना चाहिए व भ्रष्टाचार मिटना चाहिए।

☛ **लोकतन्त्र में जनता सर्वोपरि क्यों हैं? :** लोकतन्त्र में 'लोक' अर्थात् 'जनता' और 'तन्त्र' अर्थात् 'व्यवस्था'। अत: 'लोकतन्त्र' का अभिप्राय है- जनता के द्वारा चलने वाली व्यवस्था। दुर्भाग्य से आज लोकतन्त्र में जनता त्रस्त है, सरकार मस्त है। यह सच्चा लोकतन्त्र नहीं हो सकता। आज भारत के अधिकांश राजनैतिक दल, सांसद व जनता जब यह चाहते हैं कि कालाधन को वापस लाने के लिए सरकार को प्रभावी व परिणामदायक (Effective & Result Oriented) सात ठोस कदम उठाने ही चाहिए तथा भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मजबूत लोकपाल बनाना ही चाहिए तो केन्द्र सरकार को जनता की राष्ट्रहित व जनहित में न्यायपूर्ण व संवैधानिक मांग को मानना ही पड़ेगा।

☛ **केन्द्र सरकार ने कालाधन व भ्रष्टाचार के बारे में क्या किया है? तथा क्या करना चाहिए? :** यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कालाधन व भ्रष्टाचार के बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर के वित्तमंत्री तक तथा सत्ता पक्ष के अधिकांश बड़े नेता बहुत ही हल्की, गैर जिम्मेदाराना व निराशाजनक बातें करते हैं- जैसे विदेशों में हमारे देश के कानून लागू नहीं होते हैं, हम आर्मी भेजकर कालाधन नहीं मंगा सकते हैं। इसी तरह से कालाधन के स्रोतों, उसकी मात्रा व वापस लाने के उपायों के बारे में सुनियोजित तरीके से भ्रम फैलाया जाता है। कालाधन के बारे में 70 से अधिक देशों के साथ इस प्रकार की सन्धियाँ की हैं ताकि 2011 से पहले विदेशों में छुपाये धन के बारे में हम जानकारी नहीं मांग सकते हैं। हमारा प्रश्न है कि ये सन्धियाँ कालाधन लाने के लिए की हैं या कालाधन जमा करने वालों को बचाने के लिए की हैं?

कालाधन के ऊपर सरकार ने श्वेत पत्र के नाम पर झूठ पत्र प्रस्तुत किया है। भ्रष्टाचार जिसने लोकतन्त्र की जड़ों को खोखल कर दिया है। पूरी दुनियाँ में भारत की प्रतिष्ठा घटा दी है। आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। उसके बारे में सरकार की ओर से यह कहा जाता है कि- इसको रातों-रात नहीं मिटाया जा सकता है। हम कब कह रहे हैं कि एक दिन में भ्रष्टाचार खत्म कर दो। हम तो 65 सालों से इन्तजार ही कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि देश की जनता की आवाज सुनो और कालाधन लाने के लिए सात मजबूत प्रक्रियाओं तथा भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए तीन उपायों एवं व्यवस्था परिवर्तन के छ: मुद्दों पर सरकार को तत्काल प्रभाव से ठोस कदम उठाने चाहिए।

☛ **वैश्विक षड्यन्त्र :** देश की लगभग 99% जनता को लगता है कि देश व दुनियाँ जैसे सामने से दिख रही है वैसे ही सरलता, सहजता, समरसता, प्रेम, सद्भावना, समझदारी, लोकतान्त्रिक एवं न्यायपूर्ण तरीके से चल रही है। दुर्भाग्य से जैसे हमें दिख रहा है वैसे दुनियाँ नहीं चल रही है। उदाहरण के तौर पर हम चार विषय प्रस्तुत कर रहे हैं।

1. **राजनैतिक षड्यन्त्र :** भारत का प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री, विदेशमंत्री व रक्षामंत्री ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए जो अमेरिका व अमेरिकन कंपनियों तथा अन्य विदेशी कंपनियों के हित में नीतियाँ बनाने वाला हो, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों व विषयों पर अमेरिका की नीतियों का समर्थन हो, इसके लिए विदेशी ताकतें सामाजिक व आर्थिक रूप से एक लम्बी कार्ययोजना के तहत काम करती हैं। मीडिया मैनेजमेन्ट से लेकर इमेज-बिल्डिंग के लिए बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ काम करती हैं। आने वाले 5 वर्षों से लेकर 50 वर्षों तक भारत के विकास के मॉडल कैसे हों जिससे कि विदेशी कंपनियाँ अपनी तकनीक, अपनी फैक्ट्रियाँ एवं अनुसंधान उसी दिशा में करें और विदेशों की प्रतिबन्धित दवा, हथियार व अन्य उत्पाद भारत में खपते रहें, भारत एक डैम्पिंग सेन्टर बन जाए, इस प्रकार बहुत से ऐसे विषय हैं। हमारी संसद में भी अमेरिका, यूरोप व अन्य विदेशी कंपनियों तथा उन देशों के समर्थक लोगों को बाकायदा फाइनेंश करके तथा अनेक प्रकार से परोक्ष रूप से मदद करके संसद में तथा विधानसभाओं में भेजा जाता है, जिससे कि देश के जल, जंगल, जमीन, भू-सम्पदाओं पर विदेशी कंपनियों का कब्जा हो सके। F.D.I. यानी विदेशी पूँजी निवेश के जरिए विदेशी कंपनियों पूँजीपतियों व भ्रष्टाचार करके देश को लूटने वाले लोगों का भारत के सभी आर्थिक संस्थानों, रिटेल से लेकर शेयर मार्केट तक पूरी अर्थव्यवस्था पर इनका वर्चस्व कायम हो सके, इसके लिए वे बहुत ही कूटनीतिक तरीके से ये विदेशी ताकतें तात्कालिक, मध्यकालिक व दीर्घकालिक योजना के तहत काम करती हैं।

2. **आर्थिक षड्यन्त्र :** किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है वहाँ की <u>मजबूत अर्थव्यवस्था।</u> पहले देशों को भौगोलिक रूप से गुलाम बनाकर आर्थिक रूप से लूटा जाता था। अब आर्थिक रूप से गुलाम बनाने का बहुत बड़ा कुचक्र चल रहा है। इस आर्थिक लूट के चक्रव्यूह के जाल का ताना-बाना ऐसा बुना जाता है कि सामान्य व्यक्ति की समझ में तो ये बातें आ ही नहीं सकती। बड़े-बड़े बुद्धिमान लोग भी धोखा